

- सरकार अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में वृद्धि कर सकती है तथा आय उत्पन्न करने वाले पहलुओं के बजाय क्षमता निर्माण पर बल देते हुए, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहित करके आर्थिक संवृद्धि की दर को गतिशीलता प्रदान कर सकती है।
- राजकोषीय नीति आय पुनर्वितरण की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। एक वैविध्यपूर्ण और प्रगतिशील कर संरचना से आय और संवृद्धि के न्यायोचित वितरण को प्राप्त किया जा सकता है।
- राजकोषीय उपायों का उपयोग अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीतिक दबावों का प्रतिकार करने हेतु किया जा सकता है। करों और व्यय के द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रण के अतिरिक्त, राजकोषीय नीति अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों को सब्सिडी और संरक्षण सहित संरचनात्मक बाधाओं, बाजार की अपूर्णताओं तथा भौतिक नियंत्रणों के आरोपण को दूर कर सकती है।
- राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और इसकी कुल प्राप्तियों (उधार को छोड़कर) के मध्य अंतर होता है। यह समस्त स्रोतों से सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को इंगित करता है। सरकार राजकोषीय घाटे को निम्नलिखित के माध्यम से नियंत्रित कर सकती है:
 - आर्थिक अनुदानों में कमी; वेतन, भत्तों पर व्यय में कमी; पुराने कर्ज पर व्याज भुगतान में कमी आदि के द्वारा सरकार के व्यय को कम करना।
 - प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों कराधान स्रोतों से राजस्व में वृद्धि करना।
 - तीव्र आर्थिक संवृद्धि प्राप्त करना: यदि अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है, तब करों में वृद्धि किए बिना, सरकार के कर राजस्व में वृद्धि होगी।

8. Distinguish between Revenue and Capital accounts of the Budget. Discuss the significance of increasing capital expenditure for an economy.

बजट के राजस्व और पूंजी खाते के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। किसी अर्थव्यवस्था के लिए पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के महत्व की विवेचना कीजिए।

दृष्टिकोण:

- सरकारी बजट की अवधारणा का संक्षिप्त परिचय दीजिए।
- बजट के राजस्व और पूंजी खाते के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए।
- अर्थव्यवस्था के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि के महत्व की विवेचना कीजिए।

उत्तर:

सरकारी बजट एक वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जो आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अनुमानित सरकारी व्यय और अपेक्षित सरकारी प्राप्तियां या राजस्व की रूपरेखा को प्रदर्शित करता है।

भारत के बजट में राजस्व खाता और पूंजी खाता सम्मिलित होते हैं। इनके मध्य अंतर निम्नलिखित हैं:

- **राजस्व खाता:** यह सरकार की राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय को दर्शाता है।
 - **राजस्व प्राप्तियां:** राजस्व प्राप्तियां, सरकार की गैर-प्रतिदेय प्राप्तियां (non-redeemable receipts) होती हैं अर्थात् इन्हें सरकार से पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इनमें कर एवं गैर-कर राजस्व सम्मिलित होता है। कर राजस्व में केंद्र सरकार द्वारा अधिरोपित करों तथा अन्य शुल्कों से प्राप्त आय सम्मिलित होती है। गैर-कर राजस्व में मुख्यतः ऋणों से होने वाली व्याज प्राप्तियां, लाभांश और सरकार द्वारा किए गए निवेश पर लाभ, सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाओं हेतु प्रशुल्क एवं अन्य प्राप्तियां तथा विदेशों या संस्थानों से सहायता के रूप में प्राप्त नकद अनुदान सम्मिलित होते हैं।
 - **राजस्व व्यय-** सामान्यतः राजस्व व्यय न तो कोई भौतिक/वित्तीय परिसंपत्ति सृजित करता है और न ही सरकार के दायित्व को कम करता है। इसमें सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज और विभिन्न सेवाओं पर किए गए व्यय, सरकार द्वारा ऋण पर व्याज भुगतान हेतु किए गए व्यय तथा राज्यों को प्रदत्त अनुदान (भले ही कुछ अनुदान परिसंपत्तियों का सृजन कर सकता है) शामिल होता है।
- **पूंजी खाता:** इसमें सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय सम्मिलित होते हैं।
 - **पूंजीगत प्राप्तियां:** पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की ऐसी प्राप्तियां होती हैं जिनसे या तो कोई देयता सृजित होती है या वित्तीय परिसंपत्तियां कम होती हैं। इनमें सरकार द्वारा बाजार उधारियों के रूप में जनता से प्राप्त ऋण, ट्रेजरी, बिलों की बिक्री के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों से की गई प्राप्तियां और विदेशी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त ऋण तथा केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों की वसूलियां सम्मिलित होती हैं। अन्य